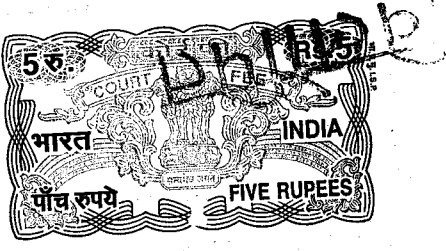


न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक/2015 पुनरीक्षण

R- 3272/I/2015



श्री दिवाकर दीक्षित
द्वारा आज दि 7-10-15 को
प्रस्तुत

~~राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर~~
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित,
7-10-15

① दिनेश पुत्र श्री अशोक जाट, आयु- 26 वर्ष,
व्यवसाय- कृषि, निवासी- कुआ खेड़ी,

तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0)

① गजेन्द्र सिंह 510 शाह सिंह
③ शरदा लाल 510 अशोक 481 आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला-
विदिशा (म0प्र0)
2. तहसीलदार, तहसील व जिला विदिशा
(म0प्र0)
3. गोरे लाल पुत्र श्री संदेर सिंह, जाति मैना,
निवासी- कुआ खेड़ी, तहसील व जिला
विदिशा (म0प्र0)
4. मनोज अहिरवार उर्फ चिकला पुत्र श्री
रेवाराम, निवासी- कुआ खेड़ी, तहसील व
जिला विदिशा (म0प्र0)
5. श्रीमती फूल वाई पत्नि स्व0 श्री प्रहलाद,
जाति सेन, निवासी- कुआ खेड़ी, तहसील व
जिला विदिशा (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

Pa
शहर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश
दिनांक 25.03.2013, प्रकरण क्रमांक 20, (अ)- 68/12-13 द्वारा
श्रीमान नायब तहसीलदार, तहसील व जिला विदिशा जिसके द्वारा
आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर 1,000/- रुपये की
धनराशि अधिरोपित कर अतिक्रमण का प्रकरण समाप्त किया गया।

आवेदक की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम
पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है, इसके पूर्व किसी भी
न्यायालय में अथवा और कहीं आवेदक द्वारा कोई पुनरीक्षण
याचिका प्रस्तुत नहीं की गई, न ही निरस्त हुई और न ही वर्तमान
में विचाराधीन है।


21/8/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - बिदिशा

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3272-एक/15

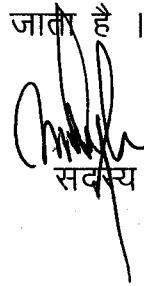
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.11.15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार जिला बिदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ-68/12-13 में पारित आदेश दिनांक 25.3.13 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिताकहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गयी है ।</p> <p>2- यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अतिक्रमण हटाये जाने की अनुमति दिये जाने बावत प्रार्थना पत्र पर प्रारंभ हुआ है । जो आवेदन आवेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है उसमें यह उल्लेख किया गया था कि अनावेदक क्रमांक-3 लगायत 5 ने आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की आराजी क्रमांक 237/1 रकवा 1.210 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है एवं गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह एवं 1/4 शारदा वाई पत्नि अशोक जो कि ग्राम कुआं खेडी प0ह0 न0 76 तहसील बिदिशा मुख्य सड़क पर स्थित है । और सड़क मार्ग पर अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 5 ने अतिक्रमण कर टपरे डालकर होटल, दुकान बना ली है, जिससे आवेदक को अपनी भूमि पर आने जाने में काफी परेशानी होती है। इसलिये अतिक्रमण को हटाये जाना आवश्यक है, उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् विचारकर माना है। कि अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 5 द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसलिये अतिक्रमण पर 1000/- रुपये की राशि अधिरोपित कर अतिक्रमण का प्रकरण समाप्त किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गयाकि विवादित भूमि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की भूमि है, यह भूमि मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है । मुख्य मार्ग पर अनावेदक क्रमांक -3 लगायत 5 ने अतिक्रमण कर टपरे बना लिये गये है जिससे वहां पर गुजरने वाले सभी व्यक्तियोंके आवागमन में काफी कठनाई होती है। ऐसा आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के</p>	

for

MM

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचार करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया कि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, हटाने के निर्देश के साथ-साथ अतिक्रमणकारियों पर 1000/- हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, किन्तु उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया है ऐसी स्थिति अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश स्पष्ट रूप से अनावेदक क्रमांक 2 तहसीलदार बिदिशा को दिये जाये तथा आवेदक की वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाये । मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि आवेदक द्वारा जो आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था । उसमें उल्लेख किया था कि मुख्य सड़क मार्ग पर आवेदक की कृषि भूमि स्थित है इसी मार्ग से आवेदक एवं अन्य लोगों को आवागमन होता है, जिसपर अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 5 ने अतिक्रमण कर टपरे बना लिये हैं, जिससे आवेदक एवं अन्य लोगों को आवागमन प्रभावित हुआ है, और तहसीलदार द्वारा एक हजार का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है, इस प्रकार अतिक्रमण प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बिदिशा को निर्देशित किया जाता है कि वह एक माह में अतिक्रमण हटायें । इस निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।
उभय पक्ष सूचित हों ।

405
2/5/2


सदस्य